प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक-10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 28-7 मार्च 2022 मूल्य पांच रूपए

गडकरी के घोषित 65000 करोड़ के 69 राजमार्गों पर कब होगा काम शुरू पूछने लगा है आम आदमी

शिमला/शैल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से 2016और 2017 में प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले 65 हजार करोड़ के निवेश से 69 राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा करने में से अब तक एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को केंद्र से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अब सरकार ने 69 राजमार्गो की जगह केवल नौ राजमार्गो के निर्माण को शुरू करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। लेकिन इनमें से भी किसी राजमार्ग को लेकर मंजूरी नहीं मिली है।

इन राजमार्गों के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सता में आने के बाद से लेकर आज तक 16 अक्तूबर 2018 को केवल एक बार पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में यह जानकारी दी व कहा कि इन राजमार्गो को लेकर वह जब भी दिल्ली जाते है तो हर बार इस मसले को उठाते है।

प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस बावत प्रश्न पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 25 राजमार्गो की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी थी ताकि इन पर प्राथमिकता के आधार काम शुरू हो सके। लेकिन अब इनमें से नौ राजमार्गो की सूची भेजी है ताकि इनका काम शुरू हो सके। उन्होंने सदन में दावा किया कि यह नौ राजमार्ग किसी न किसी तरह से 69 राजमार्गो से जुड़े हुए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 सितंबर 2016 को 61, दो जनवरी 2017 को चार और 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले दस अप्रैल 2017 को तीन और 31 अगस्त 2017 को एक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की सैंद्धातिक मंजूरी देने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि इन 69 राष्ट्रीय राजमार्गो में से 63 सड़कों की डीपीआर लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार की जा रही है जबकि तीन सड़कों की डीपीआर नेशनल हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन के पास है। दो सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गो के मानकों के मुताबिक पहले से ही तैयार है और भूतल परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने के लिए 19 जनवरी 2019 को भेज दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 63 सड़कों में से 58 सड़कों की ड्रॉफ्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट 19 अप्रैल 2018, 18 सितंबर 2019 तक भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजी गई है। यह मंजूरी के लिये मंत्रालय के अधीन विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतल परिवहन मंत्रालय ने 24मई 2019 को एक चिट्ठी लिख कर बताया कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए पूर्व में बनाए गए दिशा निर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा यह मापदंड उन सड़कों पर भी लागू होंगे जिन्हें सैंद्धातिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2016 से लेकर दिसंबर 2017 तक भाजपा ने पूरे हिमाचल में हल्ला मचा कर वोट बटोरे थे कि केंद्र सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपए के 69 राजमार्ग दिये हैं लेकिन वीरभद्र सिंह सरकार कुछ नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता से धोखा कर सता में आयी और अब 69 राजमार्गो की जगह नौ पर आ गये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन राजमार्गो के मसलों को लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही हैं व कोविड की वजह से इनके निर्माण संबंधी तमाम प्रक्रियाओं की गति धीमी हुई है।

क्या ट्रांस गिरी को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला पत्राचार से आगे बढ़ेगा

शिमला/शैल। जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा ने सदन में कहा कि जिला सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र व यहां की हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला 2018 में नामंजूर हो चुका है। लेकिन जयराम सरकार ने इस मामले को दोबारा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और अब यह मामला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास लंबित है ।

मारकंडा ने कहा कि जयराम सरकार इस मामले पर गंभीर है और इस इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए जयराम सरकार की ओर से 2018 से लेकर अब तक 14 बार पत्रचार किया जा चुका है। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार ने प्रश्न काल के दौरान पूछे गये प्रश्न के जवाब में मारकंडा ने कहा कि संविधान में जनजातीय क्षेत्र को घोषित करने के लिये उस इलाके में 50 फीसद जनजातीय आबादी होनी चाहिये और इसके अलावा क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, एक प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ा होना चाहिए।

मारकंडा ने कहा कि इस इलाके में जनजातीय आबादी केवल 0.20 फीसद ही है। इसके अलावा यहां रहने वाली आबादी में आदिम लक्षणों के संकेत व उनकी विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। भौगोलिक तौर पर यह क्षेत्र आम आबादी से बहुत दूर होना चाहिए और अन्य समुदायों से इनका मिलना जुलना बहुत कम होना चाहिए। मारकंडा ने कहा कि यह इलाका इन शर्तो को भी पूरा नहीं करता है। इसके बावजूद सरकार ने इस इलाके की हाटी जाति को जनजातीय जाति में शामिल करने के लिए एथनोग्राफिक अध्ययन कराया और सकारात्मक रिपोर्ट केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भेजी है।

मारकंडा ने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को 2016 में भेजा था लेकिन 2018 में इसे नामंजूर कर दिया गया था। मारकंडा ने कहा कि पहले यहां की आबादी जनजातीय श्रेणी में लाई जाएगी उसके बाद इस इलाके को जनजातीय घोषित किया जाता है। इस पर कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस मसले को सीधे प्रधानमंत्री से उठाये ताकि इस क्षेत्र के लोगों को जनजातीय श्रेणी के लोगों को मिलने वाले लाभों वंचित न रहना पड़े।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मसला बहुत जवलंत है और जिला सिरमौर के साथ उतराखंड के लगते इलाके जनजातीय क्षेत्र घोषित है। आधे परिवार उतराखंड में चले गए हैं और आधे परिवार हिमाचल में है। तो परिवार उतराखंड के जौनसार बावर इलाके में चले गए हैं वह जनजातीय श्रेणी में शामिल है जबकि हिमाचल में बसा परिवार जनजातीय श्रेणी में शामिल नहीं है जिस कारण उन्हें जनजातीय श्रेणी के लोगों को मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वह इस मसले को दोबारा से केंद्र सरकार के समक्ष उठायेंगे।

राज्यपाल ने विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए मंडी जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसाइटी की पहल संवेदना योजना का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर जो राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, ने मंडी जिला के सुन्दरनगर में विशेष रूप से सक्षम लोगों के घरों तक पहुंचना है। यह दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्यक्रम है और उनकी वेदना हमारी भी है। जिला प्रशासन और रेडक्रॉस

लोगों के लिए जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसाइटी की पहल संवेदना योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबंधन मंडल की सदस्य एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर भी उपस्थित थीं।

इस योजना के अन्तर्गत फिजियोथैरेपिस्ट दिव्यांग व्यक्तियों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सूचना प्रदान करेंगे और गंभीर रूप से बीमार और कोमा में चल रहे मरीजों के घर-द्वार पर पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के पास व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। योजना के अन्तर्गत जरूरतमंदों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संवेदना के नाम से प्रारम्भ की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद सोसाइटी की यह पहल लोगों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन महत्त्वपूर्ण होता है और इस पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री के विज़न को प्रस्तुत करने के लिए जिला प्रशासन प्रशंसा का पात्र है।

राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि रेडक्रॉस विश्वभर में मानवता की सेवा में कार्यरत रहती है और विशेष तौर पर आपदा के समय संगठन का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के मध्य जारी युद्ध में भी रेडक्रॉस अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहा है क्योंकि सेवा ही इसके केंद्र में है और हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। उन्होंने राज्य में सोसाइटी की जिला शाखाओं के कार्यों की भी सराहना की। राज्य रेडक्रॉस के स्वयंसेवियों को आपदा और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अपने स्तर पर देना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन की इस पहल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।

स्थानीय विधायक राकेश जमवाल ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जन कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में आम लोगों के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सुन्दरनगर के नागरिक अस्पताल की क्षमता 150 बिस्तर की कर दी गई है और 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मातृ-शिशु अस्पताल भी लोगों को समर्पित किया गया है। नागरिक अस्पताल में रेडक्रॉस के माध्यम से डायलसिस केंद्र भी स्थापित किया गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने संवेदना पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को व्हील चेयर, अल्फा बेड और श्रवण यंत्र भी प्रदान किए।

इससे पूर्व उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अरिंदम चौधरी ने राज्यपाल को हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया।

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने राज्यपाल का स्वागत किया और संवेदना योजना का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से इस अवसर पर फर्स्ट-एड पर आधारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की।

इस अवसर नगर परिषद सुन्दरनगर के अध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के 210 छात्रों को डिग्री प्रदान की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चंडीगढ़ के निकट स्थित आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज राजपुरा के 10वें दीक्षांत समारोह में 210 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। वह इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह स्वयं निर्धारित करना होगा कि वे रोजगार ढूंढने वाले बनना चाहेंगे अथवा रोजगार प्रदाता बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नही होती, बल्कि आज का यह दिन विद्यार्थी जीवन के उपरान्त नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की शुरुआत है। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों से नेतृत्व क्षमता विकसित करने और अवसरों को परखकर आगे बढ़ने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की अमूल्य संपत्ति हैं तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण कार्यों में आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। कोई भी राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है, जब युवा ऊर्जा केन्द्रित, अनुशासित और विकासोन्मुखी हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, देशभक्ति, ईमानदारी और लगन जैसे मूल्यों को विकसित करने का आग्रह किया।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल परम्परा पर आधारित रही है, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली डिग्री के बाद नौकरी की मांग करती है। अंततः हम जमीन से नहीं जुड़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल देश की युवा पीढ़ी ही इसमें परिवर्तन ला सकती है।

उन्होंने युवाओं को नवोन्मेषी विचारों के साथ आगे आने का आहवान किया ताकि समाज को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह डिग्री प्राप्त करने में बहुत से लोगों का योगदान रहता है और अब उन्हें इसका उपयोग समाज के लाभ के लिए करना चाहिए।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष डॉ. एम.पी. पुनिया ने कहा कि यह आयोजन केवल दीक्षांत समारोह भर नहीं है, बल्कि जीवन में नई चुनौतियों का आरम्भ है। आज के छात्र राष्ट्र का भविष्य हैं और हमें उन्हें अपने चुनिंदा क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही रवैया अपनाना होगा। उनमें सीखने की प्रवृति होने के साथ ही रचनात्मकता और सामाजिक समस्याओं पर विचार भी करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनने और स्वयं तथा राष्ट्र के गौरव के लिए दिन-रात मेहनत करने की सलाह भी दी।

महाराजा रणजीत सिंह विश्वविद्यालय भटिंडा के कुलपति डॉ. बूटा सिंह ने आर्यन्स समूह प्रबन्धन को बधाई देते हुए कहा कि केवल 100 विद्यार्थियों और एक महाविद्यालय से उन्होंने यहां शुरूआत की और आज वे अभियांत्रिकी, विधि, प्रबन्धन, नर्सिंग, फार्मेसी, डिग्री, शिक्षा, पैरामैडिकल सहित 8 महाविद्यालयों के माध्यम से 4 हजार से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर के जनजातीय मामलों के सचिव डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. अंशु कटारिया ने राज्यपाल का स्वागत किया और शैक्षणिक सत्र का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

आर्यन्स कॉलेज के महानिदेशक डॉ. प्रवीण कटारिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक प्रो. रोशन लाल कटारिया व रजनी कटारिया सहित प्रबन्धन से जुड़े अन्य अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

मालदीव के महालेखाकार ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। मालदीव के महालेखाकार हुसैन नियाज़ी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने पर्यटन, उद्योग, पर्यावरण, वन सम्पदा, जैव विविधता और लेखा के संबंध में चर्चा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिनिधिमण्डल का शिमला प्रवास यादगार रहेगा। उन्होंने इस अवसर पर शिमला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और यहां स्थित धरोहर भवनों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्रदेश में की जा रही प्राकृतिक खेती के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के अनेक बागवान प्राकृतिक खेती के माध्यम से सेब उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश भर में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाला अग्रणी राज्य है। उन्होंने बार्नस कोर्ट भवन जो वर्तमान में राजभवन है, के संबंध में जानकारी साझा की।

इससे पहले राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल को हिमाचली शॉल व टोपी से सम्मानित किया।

मालदीव के महालेखाकार हुसैन नियाज़ी ने अपने शिमला प्रवास को ऐतिहासिक बताते हुए राज्यपाल का धन्यवाद किया।

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला के महानिदेशक, राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के अन्तर्गत गहरा नाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं।

राज्यपाल ने मृतक की आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने भी शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये, गम्भीर रूप से घायलों को 10-10 हजार रुपये तथा मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की।

केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता सिंह पटेल और बेटी प्रतिज्ञा सिंह पटेल के साथ राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की।

इस शिष्टाचार भेंट के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में वह राज्य में विभाग द्वारा की गयी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने राज्यपाल से प्राकृतिक खेती के बारे में भी चर्चा की। प्रहलाद सिंह पटेल ने राजभवन परिसर का भी दौरा किया और इस ऐतिहासिक और विरासत भवन की सराहना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने केन्द्रीय राज्य मंत्री को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने स्मार्ट बस स्टॉप का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा के समीप सुविधा सहित लगभग 100 व्यक्तियों के खड़े होने की क्षमता से सुसज्जित है।

कैनेडी चौक पर स्मार्ट बस स्टॉप का लोकार्पण किया। शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत बने इस बस स्टॉप पर 40 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्मार्ट बस स्टॉप वर्षा शालिका, पुलिस पोस्ट, मोबाइल चार्जिंग, आरओ पेयजल और 30 लोगों के लिए बैठने की

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस बस स्टॉप का निर्माण कार्य जुलाई 2021 में शुरू किया गया था और सात महीनों के रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का विधिवत् शुभारंभ किया
देवी-देवताओं के नजराने में भी 33 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से विश्वविख्यात अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का विधिवत् शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्य देवता राज माधोराय के प्रसिद्ध मन्दिर में शीश नवाया तथा पारंपरिक शोभा यात्रा जलेब में भाग लिया जो श्री राज माधोराय मन्दिर से आरम्भ होकर पड्डल मैदान पर समाप्त हुई।

पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित लोगों ने शोभायात्रा में स्थानीय देवी-देवताओं की पालकियों को उठाकर पड्डल मैदान तक पहुंचाया। जलेब में जिला के लगभग 216 देवी-देवताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया तथा श्री माधोराय मन्दिर में पूजा-अर्चना की।

ऐतिहासिक पड्डल मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में देवी-देवताओं के चढ़ावे में भी गिरावट आयी है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बजंतरियों के मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष बजंतरियों के मानदेय पर 9.52 लाख रुपये व्यय किए गए थे जबकि इस वर्ष इस पर 19 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

इस अवसर पर उन्होंने देवी-देवताओं के राशन में 50 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इस पर 16.38 लाख रुपये व्यय किए गए थे जबकि इस वर्ष 25 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने देवी-देवताओं के नजराने में भी 33 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नजराने और मानदेय के लिए 50 लाख रुपये प्रदान किए गए थे जबकि इस वर्ष इस पर 75 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे जो प्रदेश सरकार की देव संस्कृति में अटूट श्रद्धा और विश्वास को प्रदर्शित करता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं। मंडी शिवरात्रि की पूरे देश में एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से अधिक के समय में कोरोना महामारी के कारण मेले व त्यौहारों के आयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा लेकिन अब प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि यह देश के वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई वैक्सीन के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में आरम्भ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग दो माह पूर्व अपने चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में हुए चार साल के समारोह को प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित किया तथा 11500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए।

उन्होंने कहा कि सहारा योजना, गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री हिमकेयर, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, शगुन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के लाखों लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है जिसे इसी शैक्षणिक सत्र से क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी में 175 करोड़ रुपये की लागत से शिवधाम की स्थापना की जा रही है और इसका कार्य युद्धस्तर पर जारी है। शिवधाम का कार्य पूर्ण होने पर यह राज्य में आने वाले लोगों के आकर्षण का एक प्रमुख केन्द्र होगा। उन्होंने कहा कि तुंगल क्षेत्र के कोटली में एसडीएम कार्यालय खोला गया है और मंडी में 35 करोड़ रुपये की लागत से आज संस्कृति सदन का लोकार्पण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में लोगों की सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पार्किंग परियोजना का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 27 करोड़ रुपये के कॉलेज भवन का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने पड्डल मेला मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसमें गहन रूचि प्रदर्शित की।

मुख्यमंत्री ने महोत्सव आयोजन समिति द्वारा अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर आधारित स्मारिका का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर उपायुक्त मंडी एवं अध्यक्ष अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति अरिंदम चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मंडी का शिवरात्रि महोत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस महोत्सव में 216 देवी-देवताओं को आमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्वर्णिम यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी और सात सांस्कृतिक संध्याएं इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण होंगी।

मुख्यमंत्री ने मोबाइल डेंटल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने डेंटिस्ट डे के अवसर पर ओक ओवर से मोबाइल डेंटल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 34.53 लाख रुपये की लागत की यह डेंटल वैन पाठशालाओं तथा प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में, जहां दंत चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, दंत चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह डेंटल वैन दिव्यांगजनों को चिकित्सा प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगी, जो चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं जा सकते।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस वैन में स्केलर, लाइट क्योर, कम्प्रेसर सेक्शन आदि से युक्त पूर्ण रूप से स्वचालित कुर्सी के साथ-साथ एक्स-रे सुविधा, जनरेटर, जल भण्डारण टैंक, जन सम्बोधन सेवा, वातानुकूलन सुविधा आदि भी है। उन्होंने कहा कि मोबाइल डेंटल वैन में दांत निकालने, फिलिंग, स्केलिंग, एक्स-रे, रोग निदान व उपचार, दर्द निवारण की सुविधा के साथ ही रोगियों में जागरूकता तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. रजनीश पठानिया, प्रधानाचार्य दंत महाविद्यालय शिमला और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा मामला:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से यह मामला उठाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ लगते जौनसार क्षेत्र को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे सिरमौर जिला के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का मामला एक बार पुनः केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त एवं विशेष बजट का प्रावधान सुनिश्चित होगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग भी पूरी होगी।

सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा और हाटी समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश में पिछले एक साल के दौरान जीएसटी संग्रह में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

शिमला/शैल। प्रदेश में पिछले एक साल के दौरान जीएसटी संग्रह में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। फरवरी, 2022 में हिमाचल प्रदेश में जीएसटी संग्रह 322.41 करोड़ रुपये रहा, जो फरवरी, 2021 में 276.74 करोड़ रुपये था। वर्तमान वित्त वर्ष में फरवरी, 2022 तक संचयी जीएसटी संग्रह 3826.76 करोड़ रुपये जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2856.11 करोड़ रुपये था। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी राजस्व में सकारात्मक वृद्धि पिछले कुछ महीनों में सुधार की दिशा में किए गए विभिन्न नीति और प्रशासनिक उपायों के कारण संभव हुयी है। विभाग ने जीएसटीएन द्वारा विकसित विभिन्न आईटी उपकरणों की मदद से काफी संख्या में जीएसटी चोरी के मामलों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि आईटी उपकरण संदिग्ध करदाताओं पर नजर रखने के लिए रिटर्न, चालान और ई-वे बिल डेटा का उपयोग करते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में सिस्टम क्षमता में वृद्धि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद गैर-फाइलर्स को नकारना, फील्ड कर्मियों के प्रदर्शन की निगरानी, भौतिक सत्यापन एवं ई-बिलों को ब्लॉक करना जैसी कई पहल की गयी हैं। ई-वे बिल और गैर-फाइलरों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के पारित होने से पिछले कुछ महीनों में रिटर्न दाखिल करने में लगातार सुधार हुआ है।

यूनुस ने कहा कि विभाग ने जनवरी, 2022 के महीने में हितधारकों की समस्याओं के समयबद्ध निवारण के लिये टैक्स हाट कार्यक्रम शुरू किया और साथ ही उन्हें विभाग द्वारा प्रशासित जीएसटी और अन्य संबद्ध करों के तहत होने वाले नए बदलावों से अवगत करवाया।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, व्यापार और उद्योग के मुद्दों को प्राथमिकता और शीघ्रता से हल करने के उद्देश्य से व्यापारी सुविधा प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। यह आशा की जाती है कि इन पहलों से आने वाले समय में जीएसटी राजस्व में और सकारात्मक वृद्धि होगी।

देश का पहला हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा 4 मार्च को प्रस्तुत किए गए बजट में एक बड़ी प्रतिबद्धता यह है कि राज्य सरकार अपनी शत-प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता को अक्षय और हरित ऊर्जा से पूरा करने के लिए प्रयास करेगी। यदि राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बन जाएगा।

हिमाचल में प्रतिवर्ष लगभग 12000 मिलियन यूनिट बिजली की खपत होती है। इसमें से केवल 2000 मिलियन यूनिट ताप ऊर्जा (थर्मल पावर) और शेष हरित अथवा अक्षय ऊर्जा है। राज्य को दो कारणों से ताप विद्युत का उपयोग करना पड़ता है। राज्य ने बहुत समय पूर्व ताप विद्युत केन्द्रों के साथ विद्युत खरीद समझौता किया है। इन ताप विद्युत केन्द्रों के तहत दायित्व धीरे-धीरे कम हो जाएंगे और वर्ष 2034 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इन दायित्वों में निर्धारित लागत और वास्तविक खपत शुल्क दोनों का भुगतान शामिल है। दूसरा कारण यह है कि राज्य चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने के लिए थर्मल पावर का उपयोग करता है क्योंकि इसकी लागत अक्षय ऊर्जा से कम है। हरित राज्य बनने के लिए हिमाचल प्रदेश को इन दायित्वों और आवश्यकता से बाहर निकलना होगा। यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसी की वर्तमान बजट में आकांक्षा की गयी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्लासगो में 26वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत पंचामृत के प्रमुख दो अमृत तत्व भारत की अपनी गैर- जीवाश्म ईंधन क्षमता को 50 गीगावाट तक बढ़ाने और वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता की 50 प्रतिशत पूर्ति करने की प्रतिबद्धता थी।

हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ बड़ा व बेहतर करने की है। यह पूर्ण हरित राज्य के रूप में परिवर्तित होने की इबारत लिखने का प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश को अपने ताप ऊर्जा दायित्वों की आर्थिक सुरक्षा या उन्हें खरीदे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मोल-भाव करना होगा जिसमें संभवतः जी-7 देश भी सहायक हो सकते हैं क्योंकि तभी उचित एवं न्यायसंगत मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ-साथ यह जलवायु वित्त का एक हिस्सा भी होगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर पहले ही इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष उठा चुके हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर एवं उपाध्यक्ष तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष व इसके सदस्यों के साथ चर्चा की है।

यह एक महत्वाकांक्षी परिकल्पना है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने बल्कि हिमाचल प्रदेश में निर्मित प्रत्येक उत्पाद को संपोषणीय और हरित के रूप में प्रमाणित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण व साहसिक कदम है। इससे प्रदेश में निर्मित होने वाले उत्पादों का व्यापक स्तर पर मूल्यवर्धन होगा।

ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है।

......स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

एग्जिट पोल का सच

सात मार्च को अंतिम चरण का मतदान था। इस मतदान के बाद एग्जिट पोल के परिणाम आने शुरू हो गये जो मतगणना तक चलते रहेंगे। हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल और चुनाव से पहले ओपिनियन पोल का चलन काफी अरसे से चला आ रहा है। लेकिन इनके परिणाम कभी भी पूरी तरह सही साबित नहीं हुए हैं यह भी सच है। इस परिदृश्य में यह दावे के साथ कहा जा सकता है यह पोल परिणाम सही सिद्ध नहीं होंगे। हमारा आकलन पहले भी यह रहा है कि पांचों राज्यों में भाजपा की जीत नहीं होगी। पंजाब को लेकर भी यह आकलन है कि वहां पर आप की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा यह हमारा मानना है। चुनाव परिणाम स्पष्ट कर देंगे कि किस का आकलन सही रहेगा। इसलिए आकलन का आधार क्या है इस पर अभी कोई लंबी चर्चा करने का औचित्य नहीं है।

लेकिन एग्जिट पोल को लेकर यह सामने रखना आवश्यक हो जाता है की मतगणना के दिन से शुरू होने से पहले तक पोस्टल बैल्ट आ सकते हैं। जो लोग मतदान के अंतिम दिन के बाद पोस्ट से अपना मतदान भेजेंगे उस मतदाता की एग्जिट पोल के परिणामों से प्रभावित होने की संभावना बराबर बनी रहती है। क्योंकि जब वह इन पोल परिणामों में यह देखता है कि सरकार तो अमुक पार्टी की बन रही है तो उसी के पक्ष में मतदान करना उचित रहेगा। इससे जिन उम्मीदवारों की हार जीत सौ पच्चास वोटों से हो रही होती है उनको इससे लाभ मिल जाता है। इसी कारण से यह कहना शुरू कर दिया जाता है कि बड़े कम अंतर से हार जीत होगी। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में इन्हीं पोस्टल बैल्ट से पूरा चुनावी परिणाम बदल गया था यह देश देख चुका है। इसी परिदृश्य में यह उठाया जाना आवश्यक हो जाता है कि क्या मीडिया को इस तरह का आचरण करना चाहिए? क्या इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठेंगे? जब मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो देता है तब समाज में अराजकता पनपती हैं। जो कालांतर में सबको घातक सिद्ध होती है। मीडिया के साथ ही प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व भी अविश्वसनीय हो जाता है।

आज देश ही नहीं पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने संयुकत राष्ट्र संघ से लेकर नीचे तक हर वैश्विक संस्था की प्रसंगिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिये हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानवता से ऊपर व्यापार हो गया है। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की आपदा में अपने लिये व्यापारिक अवसर तलाशने को प्राथमिकता दे रहा है। इसलिए कोई भी राष्ट्र यह युद्ध छिड़ने से पहले अपने नागरिकों को यूक्रेन से नहीं निकाल पाया। क्या सभी देशों की गुप्तचर संस्थाओं को यह युद्ध छिड़ने की संभावनाओं की पूर्व जानकारी ही नहीं हो सकी? हमारे ही मीडिया संस्थानों के विदेश में बैठे पत्रकारों को भी युद्ध की पूर्व जानकारी क्यों नहीं मिल पायी? यदि गुप्तचर एजेंसियों और मीडिया को जानकारी थी लेकिन सरकार ने उसके आधार पर अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ये ऐसे सवाल हैं जो देर सवेर उठेंगे ही। सबकी विश्वसनीयता पर यह प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि यह सब कुछ इन्हीं चुनाव के दौरान घटा और हमारा नेतृत्व इस युद्ध के साये में भी सशक्त नेतृत्व के लिये समर्थन मांग रहा था।

इन चुनाव परिणामों का देश की राजनीति पर एक बड़ा और लंबा असर पड़ेगा यह तय है। क्योंकि इन चुनावों में महंगाई और बेरोजगारी जिस हद तक लोगों ने झेली है उसके असर का भी प्रभाव इन परिणामों में सामने आयेगा। देश के किसान ने जिस तरह से तीन कानूनों का विरोध किया और सात सौ किसानों ने अपनी आहुति दी इस सबका जवाब भी यह परिणाम होंगे। एक तरह से यह चुनाव आम आदमी की समझ की परीक्षा होंगे और उसका परिणाम एग्जिट पोल नहीं होंगे।

भारत की उभरती ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी बजट

–सुब्रह्मण्यम पुलीपका, सीईओ,
नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएसईएफआई)

भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और स्थापित सौर क्षमता के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश है। फरवरी 2022 की शुरुआत में, भारत के सौर प्रतिष्ठानों ने 50 गीगावाट के मील का पत्थर पार कर लिया। इससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया। वर्ष 2021 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। अगस्त 2021 में, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, भारत ने 100 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता हासिल की। नतीजतन, दिसंबर 2021 में, भारत 150 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े हाइड्रो सहित) वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। 2021 एक ऐसा वर्ष भी है जिसमें भारत के सौर प्रतिष्ठानों ने 2020 की स्थिति की तुलना में 210 प्रतिशत की छलांग के साथ 10 गीगावाट की क्षमता को पार कर लिया। इस प्रकार, यह कोविड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत के सौर इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष साबित हुआ।

आज, भारत दुनिया के ऊर्जा संबंधी सबसे बड़े परिवर्तनकारी कार्यक्रमों वाले देशों में से एक है, जिसका लक्ष्य महत्वाकांक्षी और व्यावहारिक दोनों है। कॉप 26 में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2030 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संबंधी लक्ष्य को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। अब जबकि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ नौ वर्ष बचे हैं, बजट 2022 ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र को एक अनुकूल परिस्थिति प्रदान करने की दिशा में बेहद आवश्यक प्रोत्साहन दिया है।

बजट 2022 भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लक्ष्यों और संबद्ध सामाजिक - आर्थिक लाभों को बढ़ावा देने की दृष्टि से वाकई परिवर्तनकारी है, खासकर उस स्थिति में जब यह क्षेत्र बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधान भारतीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख आधारभूत स्तंभों - 'स्वावलंबन', 'समृद्धि', 'सशक्तिकरण' और 'शक्ति' - पर आधारित हैं।

स्वावलंबन: माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत का आहवान किया था। इसके अनुरूप सरकार ने भारत में उच्च दक्षता वाले सौर निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की। इस बजट में इस योजना के परिव्यय में 19,500 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे इस योजना का कुल परिव्यय लगभग तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह वृद्धि निश्चित रूप से सौर मॉड्यूल और सेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत की उत्पादन क्षमताओं में तेजी लाने में मदद करेगी और संभावित रूप से अगले तीन वर्षों में घरेलू उत्पादन में कम से कम 45 गीगावाट की वृद्धि कर भारत को वैश्विक सौर उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना देगी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 तक 15 प्रतिशत की रियायती कर व्यवस्था का विस्तार करते हुए आयातित सौर सेल और मॉडयूल पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) की घोषणा भी की गई। उपरोक्त सभी प्रावधान घरेलू उत्पादन को बेहद जरूरी गति प्रदान करेंगे और आयात पर एक दशक तक की निर्भरता की स्थिति में बदलाव लाते हुए भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के करीब ले जायेंगे।

समृद्धि: भारत की सौर क्षमता सात वर्षों में 17 गुना बढ़ी है और यह सिर्फ भारत सरकार के संगठित एवं सुसंगत नीतिगत उपायों के कारण ही संभव हो पाया है। इस वर्ष के बजट ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है। निवेश जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने की घोषणा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से दुनिया के एक आकर्षक केन्द्र के रूप में भारत की पहले से चली आ रही प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी। जीएसडीपी के चार प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति देने का कदम, जिसमें 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जिससे इसके त्वरित विकास को बल मिलेगा। बुनियादी ढांचे की समन्वित सूची में चार्जिंग की सघन अवसंरचना के साथ ऊर्जा संचयन प्रणाली और ग्रिड - स्केल बैटरी प्रणाली की व्यवस्था भारत में ऊर्जा संचयन को किफायती बनाने की आधारशिला रखेंगे।

सशक्तिकरण: विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और कम आबादी, सीमित संपर्क एवं बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के लिए आजीविका सृजन के लिए सहायता का प्रावधान ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक सही कदम है। यह भी रोचक है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हाल ही में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा आजीविका अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा जारी की है जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए एक समर्थ इकोसिस्टम बनाना है। केन - बेतवा लिंक परियोजना के लिए पनबिजली और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बजट में शामिल करने का कदम किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए षि और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों को एकीकृत करने के सरकार के संकल्प का एक ठोस प्रमाण है।

शक्ति: शक्ति का अर्थ है ताकत। गतिशक्ति और नारीशक्ति पर इस बजट के जोर ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक ताकत प्रदान की है। पीएम गतिशक्ति जहां भारत में आर्थिक विकास और सतत विकास से संबंधित एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, वहीं इस दृष्टिकोण के स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास की भावना से संचालित होने की माननीय वित्त मंत्री की घोषणा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक उत्साहजनक खबर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सभी, विशेष रूप से युवाओं, के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करते हुए भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में वैश्विक महाशक्मित बनाने के लिए गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकता है। इस वर्ष के बजट में नारी शक्ति के महत्व को भी मान्यता दी गई है जोकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के आशावादी भविष्य की शुरुआत है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी संशोधित सरकारी योजनाओं ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया है और बाल विकास के लिए समृद्ध वातावरण प्रदान करने वाली ये योजनाएं स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित हैं।

कुल मिलाकर, इस वर्ष का बजट कॉप - 26 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित 'पंचामृत' दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सही कदम है। इस दृष्टिकोण में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है, जोकि कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करते हुए 2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के आधे हिस्से को पूरा करेगा और 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करेगा। अंत में, 2070 तक भारत को निवल शून्य (नेट जीरो) बनाने के लिए इन सभी उपायों को एकीकृत करना होगा।

भारत के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में बैटरी भंडारण की भूमिका महत्वपूर्ण

– सुमंत सिन्हा –

स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हम पर निर्भर है और देश, तेजी से जलवायु लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। हाल के निर्णयों से पता चलता है कि राष्ट्र अपने परिवर्तनकारी बदलाव के लिए बड़े कदम उठा रहा है। कॉप 26 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता संबंधी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता एक महीने पहले हरित बजट और हाल ही में, हरित हाइड्रोजन नीति का पहला चरण।

ऊर्जा का भविष्य रोमांचक है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनियों, नीति- निर्माताओं, निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के दृढ़ और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में ऊर्जा भंडारण की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पहचान की है, जो उचित है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा (आरई) उत्पादन को मौजूदा 12-13 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल उत्पादन के एक तिहाई से अधिक करने पर विचार कर रहा है। इसके माध्यम से नौ साल से भी कम समय में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अभूतपूर्व 300 गीगाव ट की वृद्धि करना है।

अक्षय ऊर्जा, प्रकृति और उसकी अनियमितताओं एवं आकस्मिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है। इसलिए, लागत प्रभावी, तीव्र गति से और स्थायी तरीके से अक्षय ऊर्जा के इस विशाल उत्पादन को एकीकृत करने के लिए, हमें ग्रिड की आवश्यकताओं के अनुसार बिजली को अवशोषित करने, भण्डार करने और फिर पुनः प्रवाहित करने के लिए आसानी से बदलने लायक भंडारण प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने अपने भारत ऊर्जा दृष्टिकोण 2021 में कहा: 'दुनिया के लगभग किसी भी देश की तुलना में भारत को अपने बिजली प्रणाली परिचालन में आसानी से बदलने की क्षमता की अधिक आवश्यकता है।' रिपोर्ट में आगे कहा गया है: 'बैटरी भंडारण विशेष रूप से अल्पकालिक आसानी से बदलने की क्षमता के अनुकूल है, क्योंकि भारत को, दिन के मध्य में सौर-ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन और शाम की सर्वाधिक मांग के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता है।'

पिछले 10 वर्षों में, भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा की कहानी बहुत ही प्रभावशाली है। यदि केवल सौर ऊर्जा पर विचार करें, तो यह 2011 के मात्र 35 मेगावाट से बढ़कर 2021 में 35,000 मेगावाट हो गया। उद्योग ने अपनी भूमिका जरूर निभाई है, लेकिन पिछले एक दशक में हुए स्मार्ट, उत्तरदायी और अनुकूल नीति निर्माण को भी इस श्रेय का हकदार माना जाना चाहिए। चूंकि आरई राष्ट्रीय ग्रिड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, बैटरी भंडारण क्षेत्र भी अपनी भूमिका को विस्तार देना चाहता है।

बैटरी भंडारण क्षेत्रः भारत के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण

दुनिया के सबसे बड़े तालमेल वाले ग्रिडों में से एक के साथ, भारत में परिवर्तनशील उत्पादन और मांग-पैटर्न के लगातार बदलते रहने में वृद्धि देखी जा रही है, जिनकी वजह से ग्रिड संतुलन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा। मांग और आपूर्ति में ये असंतुलन मौसम-आधारित और दैनिक आधार पर, दोनों ही स्तरों में मौजूद है। मौसम- आधारित मांग को बाजार द्वारा सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाता है, दैनिक बदलावों का समाधान बैटरी भंडारण द्वारा किया जा सकता है।

दुनिया भर में, बैटरी तेजी से 'सभी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण' समाधान के रूप में उभर रही है और ग्रिड प्रबंधन के साथ-साथ बिजली क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों: वितरण, पारेषण और उत्पादन से जुड़े प्रणाली संचालकों/वितरण कंपनियों द्वारा योजना बनाने के लिए अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया में, 100 मेगावाट होर्न्सडेल पॉवर रिज़र्व कई अनुप्रयोगों जैसे आवृत्ति समर्थन, विभिन्न बाज़ारों में खरीद-बिक्री, ऊर्जा स्थानांतरण, नवीकरणीय को अनुरूप बनाना आदि एकदम नए क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त कर रहा है और छोटी अवधि में ही इसे अपनी कुल लागत वापस मिल गयी है।

कुल मिलाकर, बैटरी भंडारण का उपयोग मुख्य रूप से तीन बुनियादी अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये हैं- आवृत्ति प्रतिक्रिया प्रबंधन, ऊर्जा स्थानांतरण या विभिन्न बाज़ारों में खरीद-बिक्री और मध्य/लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण।

अच्छी खबर यह है कि, पिछले एक दशक के दौरान, बैटरी भंडारण की लागत में तेजी से कमी आई है और निकट भविष्य में और कमी आने की उम्मीद है। यूएस और यूके जैसे देशों में पहले से ही उदाहरण मौजूद हैं, जहां बैटरी भंडारण ग्रिड नेटवर्क के उतार-चढ़ाव और विश्वसनीयता का आर्थिक रूप से व्यवहार अनुकूल स्रोत प्रदान करती है।

व्यापक और संकेत देने वाले अवसर

भारतीय बैटरी भंडारण की मांग में बिजली-संचालित परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ अन्य भंडारण आवश्यकताओं तेजी आयेगी। नीति आयोग के अनुसार, भारत का बैटरी भंडारण बाजार 2030 तक 1000 गीगावॉट/घंटा से अधिक होने की उम्मीद है, जो वर्तमान के मामूली स्तर से बढ़कर कुल बाजार मूल्य के रूप में 250 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा।

1000 गीगावॉट/घंटा में से, अकेले बिजली क्षेत्र की मांग करीब 150 गीगावॉट/घंटा होने की उम्मीद है, इससे परियोजनाओं में 60 बिलियन डॉलर का पूंजी निवेश होगा। कुल 1000 गीगावॉट/घंटा क्षमता की स्थापना के लिए, हमें अगले पांच से छह वर्षों में लगभग 16.5 बिलियन डॉलर के विनिर्माण निवेश की आवश्यकता होगी। यह प्रति वर्ष लगभग 150 गीगावॉट/घंटा की क्षमता में तब्दील हो जाएगा, जिससे विनिर्माण और निर्माण में हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

वैश्विक अनुभव, स्थानीय सीख?

बैटरी भंडारण निर्माण में वैश्विक क्षमता, पिछले एक दशक में सात गुना बढ़ी है। चीन की 78 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि जापान और कोरिया बहुत छोटे हिस्सेदार हैं। बैटरी निर्माण के लिए एक प्रमुख निवेश केन्द्र के रूप में यूरोप भी तेजी से उभर रहा है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, अभी कुल विनिर्माण क्षमता लगभग 1,500 गीगावॉट/घंटा है। उम्मीद है कि यह 2030 तक बढ़कर लगभग 4,700 गीगावॉट/घंटा हो जाएगा। वर्तमान में, चीन अकेले कुल विनिर्माण क्षमता का लगभग 75 प्रतिशत (1,100 गीगावॉट/घंटा) का हिस्सेदार है और आगे भी प्रमुख हिस्सेदार बना रहेगा, लेकिन इसकी हिस्सेदारी में कमी आने की संभावना है, जो नए दशक की शुरुआत तक कम होकर 64 फीसदी रह सकती है। चिली, पेरू और बोलीविया जैसे देशों में महत्वपूर्ण खनिज खदानों के स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ के जरिये, चीन ने दुनिया के बाकी देशों की तुलना में यह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल किया है।

जहां तक यूरोप की स्थिति है, विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला चीन की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन बैटरी की मांग बढ़ रही है और कई गीगा-कारखाने जल्द ही सामने आएंगे। यह मांग, बिजली संचालित परिवहन प्रणाली तथा ग्रिड-स्केल भंडारण को अपनाने से प्रेरित है। यूके, फ्रांस एवं जर्मनी जैसे देशों में सहायक सेवाओं के लिए स्पष्ट और सुस्थापित बाजार हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण के उपयोग करने की आवश्यकता है।

भारत के लिए चुनौतियां

भारत नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अक्षय ऊर्जा में विस्तार कर रहा है और इसके लिए बैटरी भण्डारण एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि, चीन और यूरोप सहित वैश्विक पृष्ठभूमि को देखते हुए, विभिन्न चुनौतियों का समाधान जरूरी है:

भंडारण के लिए सही मूल्यांकन

निवेश को आकर्षित करने और एक सक्षम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, यह आवश्यक है कि बैटरी भंडारण परियोजनाएं निवेश अनुकूल होने के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त करें। दुनिया भर में, इस तरह की परियोजनाओं को राजस्व के विभिन्न आय स्रोत जैसे आवृत्ति प्रबंधन सेवाओं, कीमत के उतार-चढ़ाव संबंधी बाजार संचालन और एक ही परिसंपत्ति से अक्षय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता को नियंत्रित करने आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, भारत में, इनमें से अधिकांश उपयोग के कार्य या तो मौजूद नहीं हैं या निजी निवेश के लिए नहीं खोले गए हैं या भंडारण परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए उचित आय प्रदान नहीं करते हैं।

उच्च अग्रिम लागत

ऊर्जा भंडारण एक गैर-उत्पादक संपत्ति है और इसकी लागत को कम करने की कोई भी पहल इसे व्यावहारिक बनाने में मदद करेगी। हालांकि, बैटरियों पर वर्तमान में करों और शुल्कों के साथ भारी टैक्स लगाया जाता है, जो कुल मिलाकर 40 प्रतिशत से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप बिजली दरों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है।

कच्चे माल के लिए और योजनाएं बनाने की आवश्यकता

बैटरी निर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला को चार अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है:कच्चे माल का खनन(कच्चे माल का शोधन(सेल निर्माण(और मॉड्यूल को पैक करना। सेल निर्माण और बाद में, बैटरी में उपयोग के कच्चे माल के परिशोधन को मोटे तौर पर पीएलआई योजना में शामिल किया है, भारत में लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कच्चे माल की नियमित व आसान उपलब्धता को मुख्य चुनौती के रूप में देखा जा सकता है।

आगे का रास्ता?

भंडारण के लिए बाजार निर्माण

भंडारण का प्रभावी उपयोग, न केवल उत्पादन परियोजनाओं के साथ बल्कि पारेषण और वितरण सहित पूरे बिजली इकोसिस्टम के सभी स्तरों पर होता है। जहां कहीं भी बैटरी भंडारण लगाया जाता है, अधिकतम परिसंपत्ति उपयोग के लिए अनुप्रयोगों के पूरे मूल्य को प्राप्त करना सबसे जरूरी होता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा भंडारण के लिए कई अनुप्रयोगों को विकसित करने और उनके लिए बाजार बनाने के लिए सही नीतियां तैयार की जाएं।

इसके अलावा, चूंकि भंडारण प्रणालियों की लागत में भारी कमी आई है, और यह जारी भी रहेगी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि लंबी अवधि के लिए योजना बनाते समय, भंडारण सेवाओं के लिए भागीदारी के अवधि छोटी रखी जाए।

कर और शुल्क में छूट

जैसे केंद्र सरकार ने पूंजीगत उपकरणों के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर रियायत/छूट देने के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक मजबूत संभावित मांग बनाने में मदद की, बैटरी भंडारण के लिए भी इस सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए। सरकार ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सबसे कम जीएसटी श्रेणी (5 प्रतिशत) में रखने और शुरुआती कुछ वर्षों में आयात शुल्क को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भर होने के साथ टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, पारेषण छूट और ब्याज दर सब्सिडी से उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत को कम रखने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, शुरुआती कुछ परियोजनाओं के लिए, निवेशकों और ग्रिड संचालकों को आकर्षित करने के लिए लागत-आय अंतर के सन्दर्भ में वित्तीय सहायता पर विचार करना उचित होगा। इसके साथ ही, और भंडारण संचालकों के लिए नियमित राजस्व प्राप्ति को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए, अगले तीन से पांच वर्षों के लिए भंडारण प्रणाली से भेजी गई ऊर्जा की प्रत्येक इकाई के लिए, अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किए जा सकते हैं।

रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकियों की सम्पूर्ण श्रेणी

सरकार उन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला पर विचार कर सकती है, जिनका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के रूप में हो सकती है। एक ऐसे इकोसिस्टम पर विचार किया जा सकता है, जो वैकल्पिक भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे कि फ्लो बैटरी, सोडियम आयन, सोडियम सल्फर और संपीड़ित वायु ऊर्जा प्रणालियों के विकास को सक्षम बनाता है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रौद्योगिकियां सोडियम, सल्फर, वैनेडियम, स्टील और आयरन जैसे खनिजों का उपयोग करती हैं जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह अधिक उत्सर्जन वाली आपूर्ति की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम करती है।

सोडियम आयन जैसी भंडारण तकनीकों का उपयोग कम से मध्यम अवधि के भंडारण के लिए किया जाता है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी की लिथियम की तुलना में लागत कम होती है। सोडियम सल्फर बैटरी आम तौर पर चार से छह घंटे ऊर्जा अधिकतम स्थानांतरण को पूरा कर सकती है। संपीड़ित ऊर्जा भंडारण लंबी अवधि के भंडारण की जरूरतों को पूरा करता है- छह घंटे से अधिक की अवधि के लिए- जो अति महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं और प्रदूषण फैलाने वाले बड़े डीजल के बदले उपयोग में लाये जा सकते हैं।

भारत अपनी संपूर्ण विद्युत संरचना का पुनर्गठन कर रहा है, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों और उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भंडारण समाधानों की सम्पूर्ण श्रृंखला की आवश्यकता होगी।

विनिर्माण इकोसिस्टम के अलावा, गुणवत्ता एकीकरण और मज़बूत सॉफ्टवेयर विश्लेषण के साथ प्रदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करने सहित तैनात किये जाने से सम्बंधित संरचना विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह अनुमान लगाते हुए, पूरी दुनिया में बैटरी भंडारण की अग्रणी कंपनी, यूएस की फ्लुएंस, स्थानीय भंडारण समाधान प्रदान करने के लिए, रीन्यू पावर के साथ भागीदारी में भारत में संयंत्र स्थापित कर रही है।

यह स्पष्ट है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के लिए बैटरी भंडारण महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, नीति निर्माताओं को नीति निर्माण संबंधी अपने प्रेरक अभियान को जारी रखने की आवश्यकता है, जैसा कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पवन और सौर ऊर्जा के लिए किया है। हाल के बजट और हरित हाइड्रोजन के लिए भी नीतियां बनायी गयी हैं। इसे अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है कि जब नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, तो किन कारकों से ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित होगी। कई विकल्प हैं, जैसे करों और शुल्कों में कमी, एक स्थानीय विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण आदि, जिनका उपयोग बाद में राजकोषीय लाभों को क्रमिक रूप से कम करने के लिए किया जा सकता है। बैटरी इकोसिस्टम के विकसित होने के साथ सरकार और उद्योग को भी एक स्थायी दृष्टिकोण अपनाने को लेकर विचार करना चाहिए।

भारत द्वारा ऊर्जा के नए विकल्पों को अपनाने और कार्बन-उत्सर्जन कम करने के संकल्प में बैटरी भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार ने अपनी इच्छा और कार्य-क्षमता लोगों के समक्ष रखी है। शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। भारत ने केवल एक दशक में अक्षय ऊर्जा की क्षमता में 150 गीगावॉट की वृद्धि की है, जिसे किसी भी पैमाने के सन्दर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जा सकता है। उद्योग जगत के साथ-साथ अन्य हितधारकों को भारत को एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए, ताकि तेज विकास और हमारे लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम मिल सकें। यह अब कोई विकल्प नहीं है। यह बहुत जरूरी है।

सुमंत सिन्हा रीन्यू पावर के अध्यक्ष और सीईओ तथा एसोचैम के अध्यक्ष-नामित हैं।

मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 पर वर्चुअल जन संवाद को सम्बोधित किया

शिमला/शैल। वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास पर केन्द्रित है और इसमें प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में आवश्यकता आधारित सुधार तथा अनेक योजनाओं के आकार में वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पीटरहॉफ में बजट 2022-23 पर आयोजित वर्चुअल जन संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रथम अवसर है जब प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त कोई मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे तौर पर रू-ब-रू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद वर्गों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना रहा है। प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं, नीतियां तथा कार्यक्रम समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को समर्पित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का सबसे पहला निर्णय वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य निर्णय निराश्रित पशुओं को उचित आश्रय सुनिश्चित करवाने के लिए लक्षित था। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्यों तथा गौ-सदनों में प्रत्येक पशु के लिए 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे थे जिसे वर्ष 2022-23 के बजट में बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह प्रति पशु किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का दो वर्षों से अधिक का कार्यकाल कोरोना महामारी से प्रभावित रहा है। उन्होंने कहा कि सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश ने राज्य के लोगों तथा केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग और समर्थन से इस महामारी से निपटने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस माह की चार तारीख को 51,365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तथा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया गया। महामारी के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण पिछली सरकार की तुलना में काफी कम है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट में सभी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को कम करते हुए बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब 1000 रुपये प्रतिमाह, 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह तथा 1500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे पेंशनरों को 1700 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भी बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि अब 7.50 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा तथा इस पर कुल 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रथम अवसर है जब अन्य बजट दस्तावेजों के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गयी है। सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं, जलवाहक (शिक्षा विभाग), जल रक्षक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैराफिटर तथा पम्प ऑपरेटरों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है।

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 9000 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4600 रुपये, आशा कार्यकर्ताओं को 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7850 रुपये, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को 3400 रुपये, जलवाहक (शिक्षा विभाग) को 3800 रुपये, जल रक्षक को 4400 रुपये, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को 3800 रुपये तथा पैराफिटर व पम्प ऑपरेटरों को 5400 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपये बढ़ाकर इसे 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को भी न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गयी है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक अतिरिक्त निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत अब पंजीकरण वर्षभर किया जाएगा तथा इसका नवीनीकरण तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र थे, जबकि आज राज्य में 48 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 60 यूनिट तक बिजली की खपत पर जीरो बिलिंग करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 4.50 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि किफायती बिजली एक रुपये प्रति यूनिट की उपदान दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे 61 से 125 यूनिट तक की खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा 4 मार्च को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2022-23 के बजट की सराहना करते हुए बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गत चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने पांच बजट में 97 नई योजनाएं शुरू की गई।

इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पन्डा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन शिमला में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी मंत्री, विधायक, भाजपा नेता और प्रदेश की जनता ने वर्चुअल माध्यम से जन संवाद में भाग लिया।

परिवहन निगम में कार्यरत 631 पीस मील वर्कर्स को अनुबंध पर तैनाती

शिमला/शैल। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्यरत पीस मील वर्कर्स को अनुबंध पर लाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास की भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2011 से निगम में कार्यरत इन पीस मील वर्कर्स की चिरलम्बित मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 तथा उसके बाद निगम में आवश्यकतानुसार इन पीस मील वर्कर्स की तैनाती की गयी थी। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अब इनकी सेवाओं को परिवहन निगम में अनुबंध पर करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में आईटीआई और नॉन-आईटीआई तथा दूसरे क्षेत्रों में पीस मील वर्कर्स कार्यरत हैं। इसके लिए हाल ही में तैयार नीति के अनुरूप कुल 823 पीस मील वर्कर्स में से 631 को प्राथमिकता के आधार पर अनुबंध पर तैनाती दी गयी है जबकि शेष वर्कर्स को इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत उनकी दक्षता के अनुसार अनुबंध पर लाया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार विभाग में 49 लोगों को करूणामूलक आधार पर रोजगार देने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का लाभ सभी पात्र लोगों को सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।

कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास को बजट में प्रमुखता देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में जन सेवा के लिए समर्पित प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में सभी वर्गों के समान विकास के लिए समुचित प्रावधान किए हैं। विशेष तौर पर कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास के लिए बजट में प्रमुखता दी गयी है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने सम्बल प्रदान किया है, जोकि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गयी किसान हितैशी योजनाओं के कारण ही संभव हो सका है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं और प्रधानमंत्री द्वारा भी इस क्षेत्र में हिमाचल के प्रयासों को सराहा गया है। इस बजट में प्रदेश में 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की सभी 3615 पंचायतों में प्राकृतिक कृषि का एक-एक मॉडल विकसित कर आस-पास के किसानों को प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में परिवर्तित करने और प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के पंजीकरण का प्रावधान भी सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जा रहा है। आगामी वर्ष में 20 और एफपीओ गठित करने का प्रावधान किया गया है, जिनमें से 10 केवल प्राकृतिक कृषि पर आधारित होंगे। पराला मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने के लिए 60.93 करोड़ रुपये की लागत से 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता का नया कोल्ड स्टोर स्थापित होने से उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। जायका चरण-2 परियोजना में 13 मार्केट यार्डों को सुदृढ़ करने के लिए 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हींग व केसर की प्रायोगिक खेती के उपरान्त अब प्रदेश में दाल-चीनी एवं मौंक फ्रूट की खेती पायलट आधार पर प्रारम्भ करने से कृषि क्षेत्र में विविधता आएगी। मक्की और गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने तथा प्रदेश की पहाड़ी किस्मों के संवर्धन के लिए बीज उपदान के वर्तमान आवंटन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने व अन्य फसलों के उत्तम बीज उपलब्ध करवाने के लिए 3 करोड़ रुपये की घोषणा से किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा।

उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 2022-23 के बजट में 583 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से किसानों की आय में आशातीत बढ़ोतरी के साथ ही उनकी खुशहाली की नयी राहें प्रशस्त होंगी।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए कृतसंकल्प प्रदेश सरकार के प्रयासों से गौशालाओं तथा गौसदनों में गौवंश की संख्या 6 हजार से बढ़कर 20 हजार हो गयी है। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में 5 बड़े गौ-अभयरण्यों एवं गौसदनों की स्थापना, हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने तथा गौसदनों में आश्रित गौवंश के लिए गोपाल व्यवस्था के अन्तर्गत अनुदान 500 से बढ़ाकर 700 रुपये करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत चार वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के लिए दूध खरीद मूल्य में 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसे निरन्तरता प्रदान करते हुए आगामी बजट में भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी से दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि शिमला के दत्तनगर तथा मण्डी के चक्कर में प्रतिदिन 50 हजार लीटर क्षमता के दो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने, पशुपालकों की सुविधा के लिए 44 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस चलाने के लिए 7 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण बैकयार्ड भेड़ विकास योजना के अन्तर्गत 2 हजार भेड़ इकाइयां स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपये के प्रावधान से पशुपालकों की आर्थिकी और सुदृढ़ होगी।

ऐतिहासिक व आम आदमी का बजट:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को ऐतिहासिक और आम आदमी का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट व्यावहारिक है और सभी वर्गों को इस बजट से लाभ होगा।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरम्भ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट सत्र में शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी, पात्रता एवम् अन्य शर्तों से सम्बन्धित, विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां मनरेगा कि तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्नत शहरों के सपने को पूरा करने में यह योजना जो कि जल्दी कानून का रूप लेने वाली है, कारगर सि) होगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री का वृावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष करने पर आभार व्यक्त किया। पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40000 अतिरिक्त पात्र लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहें हैं, की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी। दिव्यांगजनों व विधवाओं को दी जा रही पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृ)जनों की पेंशन को 1500 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

सरकारी अथवा वन भूमि पर निर्मित मन्दिरों के नाम भूमि हस्तांतरित करने पर विचार करेगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी के संस्कृति सदन में आयोजित कारदार संघ की बैठक को संबोधित करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार ऐसी सरकारी अथवा वन भूमि जिस पर मन्दिर निर्मित किए गए हैं, को उनके नाम हस्तांतरित करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शहर वास्तव में देवी-देवताओं की भूमि है और तभी इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के प्रत्येक गांव का अपना देवता और उनका मन्दिर होता है। उन्होंने कहा कि मंडी के अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सैंकड़ों देवी-देवता अपने देवलुओं के साथ भाग लेते हैं मगर उन देवलुओं के ठहरने के लिए स्थान का अभाव काफी समय से बना हुआ था। उन्होंने कहा कि संस्कृति सदन का निर्माण उनकी इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए देव सदन कुल्लू की तर्ज पर किया गया है जहां हर वर्ष अन्तरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव आयोजित किया जाता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोगों की देवी-देवताओं में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने देव समाज से नशे की समस्या को दूर करने में आगे बढ़कर अपना सहयोग देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस सामाजिक कुरीति से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें पहल करनी होगी। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बजंतरियों को सामूहिक देवधुन के आयोजन का भी सुझाव दिया। उन्होंने देव समाज से स्वच्छता अभियान में सहभागिता का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि मन्दिर समितियों को राज्य में गौ-अभ्यारण्य एवं गौ-सदनों के संचालन जैसी अन्य समाजिक गतिविधियों में भी आगे आना चाहिए। उन्होंने संस्कृति सदन की आगन्तुक पुस्तिका में अपनी टिप्पणी भी लिखी।

सर्वदेवता सेवा समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बजंतरियों के मानदेय में 100 प्रतिशत और देवताओं के नजराने में 33 प्रतिशत वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संस्कृति सदन के लोकार्पण के लिए भी उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर देवी-देवताओं के मंदिर काफी अरसे से निर्मित किए गए हैं और ऐसे में यह भूमि देवताओं के नाम पर हस्तांतरित की जानी चाहिए।

जल शक्ति मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला में जल शक्ति मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 17.28 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कुनेक्शन (एफएचटीसी) हैं और वर्ष 2022 के दौरान 1.25 लाख एफएचटीसी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति के सभी घरों में नल के माध्यम से पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है और इस मिशन के तहत ऊना एक आकांक्षी जिला है। उन्होंने कहा कि 24 खण्डों, 2284 ग्राम पंचायतों और 14,525 गांवों को अब हर घर जल से जोड़ा जा चुका है। जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यात्मकता आकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश समग्र कार्यक्षमता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है और एफएचटीसी कवरेज में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सभी घरों में नल से पानी का कुनेक्शन निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है और इस दिशा में मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा, निदेशक ग्रामीण विकास ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति और प्रमुख अभियन्ता जल शक्ति ई.संजीव कौल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण का पहला फ्लाईंग स्कूल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा) डॉ. रजनीश ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए पहला फ्लाईंग स्कूल कांगड़ा जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुर में स्थापित किया जाएगा जिसके लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल और केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय की स्वायत्तशासी संस्था इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह संस्थान सरकारी कर्मचारियों के साथ ही आम लोगों का भी ड्रोन के उपयोग के बारे में मार्ग-निर्देशन करेगा और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वर्ष 2022-23 के बजट संबोधन में राज्य में चार ड्रोन फ्लाईंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश में ड्रोन सुविधा का उपयोग दवाईयों की आपूर्ति, कृषि, वानिकी, राहत एवं बचाव, निगरानी, यातायात व मौसम संबंधी निगरानी, अग्निशमन, व्यक्तिगत उपयोग, ड्रोन आधारित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में किया जा सकेगा। यह प्रदेश में संसक्त, स्वचालित और तीव्र सम्भार तंत्र (लॉजिस्टिक्स) की सुविधा भी प्रदान करेगा।

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में उम्मीदवारों को जमीनी प्रशिक्षण के लिए भूमि और भवन तथा सिम्यूलेटर की स्थापना के लिए एक कमरा उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने राज्य के 100 सरकारी कर्मचारियों को तीन वर्षों के लिए 15 प्रतिशत विशेष रियायत प्रदान करने और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बीपीएल श्रेणी के 100 छात्रों एवं प्रशिक्षुओं को तीन वर्षों के लिए श्रेणी एक, लघु, मल्टी-रोटर प्रशिक्षण 55 हजार रुपये व 18 प्रतिशत जीएसटी की दरों पर प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। इस अवसर पर उप-सचिव तकनीकी शिक्षा ललित विक्रम गौतम, अतिरिक्त निदेशक (आईटी) राजीव शर्मा व ड्रोन प्रशिक्षक चिराग शर्मा भी उपस्थित थे।

पंजीकृत सरकारी व गैर सरकारी फल पौधशाला से ही पौधे क्रय करें

शिमला/शैल। निदेशक, उद्यान डॉ. आर.के. परुथी ने फल पौधशाला उत्पादकों एवं बागवानों से आग्रह किया है कि वे विभाग के साथ पंजीकृत सरकारी व गैर सरकारी फल पौधशाला से ही पौधे क्रय करें और बाहरी राज्य से फल पौध सामग्री का अनाधिकृत ढंग से आयात और विक्रय न करें।

उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के संज्ञान में आया है कि गैर पंजीकृत फल पौधशाला उत्पादक प्रायः दूसरे प्रदेशों से अनाधिकृत तौर पर फल पौधे, मूलवृंत एवं फल पौध की कलमों का आयात कर रहे हैं और इसे कम दाम पर प्रदेश के बागवानों को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2015 और नियम, 2020 के अनुसार यह गैर कानूनी है क्योंकि बाहरी प्रदेशों से आयात किए जाने वाले पौधों से रोग एवं कीटों के फैलने का अंदेशा रहता है और फल उत्पादन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि बिना लाईसेंस के कोई भी व्यक्ति व बागवान यदि अप्रमाणित फल पौधें और कलमों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खंड स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारी उनके विरूद्ध नर्सरी पंजीकरण अधिनियम, 2015 और नियम, 2020 के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए निदेशक उद्यान विभाग की ओर से प्रदेश के सभी क्षेत्रिय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (उप-निदेशक उद्यान, विषय वस्तु विशेषज्ञ व उद्यान विकास अधिकारी) को हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2015 की धारा (23) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है।

राज्य में वर्ष 2025 तक 15 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारितःबिक्रम सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2022 में प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को विद्युत गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में वैश्विक केन्द्र बनाना है तथा विद्युत चालित वाहनों के लिए सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग की आधारभूत संरचना को तैयार करना है।

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मार्च, 2022 से मंडी के पड्डल मैदान में अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस प्रदर्शनी में बढ़-चढ़ भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन का हब बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में वर्ष 2025 तक 15 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदर्शनी में लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। इस प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक वाहनों के विभिन्न मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यह वाहन सभी प्रकार की टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष बल मिलता है, क्योंकि इनके प्रयोग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का रख-रखाव खर्च कम होता है और पेट्रोल और डीजल वाहनों की अपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रति किलोमीटर खर्च कम होता है। उन्होंने कहा कि छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को घर पर ही बिजली के सॉकेट से जोड़ कर चार्ज किया जा सकता है और यह पेट्रोल, डीजल और गैसोलिन की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी कई वर्षों तक चलती है और इन वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण न के बराबर होता है।

7 मार्च से 13 मार्च, 2022 तक प्रदेश में पेंशन सप्ताह का आयोजन

शिमला/शैल। श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ने बताया कि केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार 7 मार्च से 13 मार्च, 2022 तक पेंशन सप्ताह/पेंशन शपथ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य के सभी उपायुक्तों से जिला स्तर पर गठित कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया गया है। उपायुक्त इन समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं। इस सप्ताह के दौरान असंठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा 20 हजार पात्र श्रमिकों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या इससे कम है, इसके पात्र होंगे। योजना में लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये मासिक अंशदान देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

यदि शिक्षकों की मांगे इस बजट में पूरी हो गयी हैं तो फिर आन्दोलन क्यों

भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के यशोगान से उठी चर्चा क्या अन्य संगठनो की मांगे जायज नहीं हैं उठने लगा है सवाल

शिमला/शैल। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा एंव हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रान्त महामंत्री ड मामराज पुंडीर ने शिमला में संयुक्त प्रैसवार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा ऊना जिला में आयोजित चतुर्थ प्रांत अधिवेशन में सौंपे गए 42 सूत्रीय आग्रह पत्र तथा मंडी के कंसा चौक में आयोजित पंचम प्रांतीय अधिवेशन में सौंपे गए शेष बची मांगों हेतु 14 सूत्रीय आग्रह पत्र में से अधिकतर मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से कार्य करता है जिसका सेवा क्षेत्र संपूर्ण भारत में 28 प्रांतों, 7 केन्द्र शासित राज्यों और 120 से अधिक स्वायत्त विश्वविद्यालय हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देश में प्रतिष्ठित ऐसा शैक्षिक संगठन है जिसे राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित, शिक्षक हित और समाज हित में सेवा करने के कारण एक ट्रस्ट का दर्जा भी प्राप्त है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारत भूमि के अमर सपूतों और पथ प्रदर्शकों की प्रेरणा से निरन्तर राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित, शिक्षक हित और समाज हित में इस ध्येय से चिंतनतशील एवं कर्तव्यशील है कि राष्ट्र के संसाधनों पर यहां रहने वाले हर नागरिक का समान अधिकार है। राष्ट्र के प्रति सबके समान कर्तव्य भी है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी के कथानानुसार हर भारतीय के लिए सबसे पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

ऐसे संतो की प्रेरणा से ही श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने नारा दिया 'राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम' और तत्कालीन प्रचलित नारे 'हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो' का पूर्णतया खंडन किया।

राष्ट्र प्रथम के ध्येय को लेकर चलने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति को और अधिक परिष्कृत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सम्पूर्ण प्रारूप महासंघ के सहयोग किया गया और 2021 में इसे लागू भी दिया। यह राष्ट्रीय विचारों से ओत प्रोत सभी संगठनों और महासंघ की ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भविष्य के भारत की नींव को और अधिक मजबूत करेगी।

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह पर प्रदेश में भी सरकार ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालयों में भी शुरू करने का निर्णय लिया, सरकारी विद्यालयों को प्रभावी शिक्षा मंदिर बनाने के लिए अटल आदर्श विद्यालय योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं शिक्षा के क्षेत्र में समाज के सहयोग के लिए अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, विद्यांजलि जैसी उत्कृष्ट योजनाओं को प्रारंभ किया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह पर ही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क वर्दी व पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई। विद्यालयों में मल्टी टास्क वर्कर के पद सृजित करना, टेट की शर्त आजीवन करना, ए सी आर को ऑनलाइन करना, जे बी टी और सी एंड वी की दूसरे जिलों में नियुक्ति की स्थिति में अपने गृह जिला में स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि शर्त 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करना जिसमें अनुबंध काल भी शामिल है। सभी कर्मचारियों के लिए अनुबंध की सेवा शर्त पहले 5 वर्ष से 3 वर्ष और फिर 3 वर्ष से 2 वर्ष की गई। तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग को 2016 से 2021 तक लंबित रखा गया जबकि हिमाचल सरकार द्वारा पंजाब सरकार की अधिसूचना के साथ ही हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह पर तुरंत हिमाचल में लागू किया गया। तत्पश्चात 15% सीधे वेतन वृद्धि का विकल्प और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए महंगाई भत्ते के बराबर 31% मंहगाई भत्ता भी महासंघ के तर्कसंगत आग्रह पर प्रदान किया गया। नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार जारी 2009 की अधिसूचना को हिमाचल में भी लागू किया गया जिसके अनुसार सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु के बाद पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप ही पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृति ग्रेच्युटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।

शास्त्री एवं भाषा अध्यापकों को टी जी टी पदनाम दिया गया जो राष्ट्रभाषा और सभी भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत का सम्मान और गौरव बढ़ाता है। प्रवक्ता स्कूल न्यू का पदनाम प्रवक्ता बहाल कर दिया गया है। 2555 एस एम सी अध्यापकों के वेतन में वृद्धि सहित उनकी सेवाओं को निरंतर रखना तथा तर्कसंगत नीति बनाना, 20 वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना और उन्हें शिक्षा विभाग में समाहित करने का आश्वासन, 26.04.2010 से पहले नियुक्त प्रशिक्षित कला स्नातक शिक्षकों व प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक एवं प्रधानाचार्य बनने के लिए दोनों विकल्पों को बहाल करवाना हिमाचल शिक्षक महासंघ की बड़ी उपलब्धियां हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए शिक्षा क्षेत्र का बजट 16: कर दिया गया है जो कि अब 8412 करोड़ बनता है। यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। विद्यार्थियों के हर वर्ष दी जाने वाली छात्रवृतियों की राशि और संख्या दोनों बढ़ा दी गई है जो छात्र हित में सरकार का बहुत बड़ा फैसला है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आग्रह पर ही केंद्र सरकार के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है एवं मानव संसाधन विकास मंत्री अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री के साथ तीन बैठकें की गई जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना समीक्षा समिति का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु समिति गठित कर दी गई है जो शीघ्र अति शीघ्र अपना कार्य पूरा कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाने के लिए महासंघ ने पहले भी भरसक प्रयास किया है और इसे सरकार से लागू करवाने का पुरजोर आग्रह करता है। साथ ही एस एम सी अध्यापकों, व्यवसायिक शिक्षकों, आउटसोर्स कर्मियों, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति बनकर उन्हें नियमित करवाना, डी पी ई के लिए प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का पदनाम दिलवाना, प्राथमिक स्तर पर हर कक्षा के लिए एक शिक्षक, केंद्र पाठशाला के स्तर पर एक क्लर्क की पोस्ट सृजित करवाना, पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षक एवं आंगनवाड़ी की तर्ज पर सहायिका का पद सृजित करवाना तथा विद्यालयों में स्टाफ की संपूर्ण व्यवस्था सहित छात्र हित, शिक्षा हित और शिक्षक हित में आवश्यक हर मांग को समयानुसार पूरा करवाने का प्रयास हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ करता रहेगा।

मजदूरों का हड़ताल अधिकार खत्म होने के बावजूद बी.एम.एस.उतरा सरकार की प्रशंसा में

शिमला/शैल। 29 नवंबर 2021 को शिमला चलो सरकार को जगाओ कार्यक्रम के बाद सरकार के साथ भारतीय मजदूर संघ की लगातार बैठके होती रही। 8 फरवरी 2022 को हुई भारतीय मजदूर संघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री 4 घंटे तक बैठक में उपस्थित रहे और भारतीय मजदूर संघ की मांगों को गंभीरता से सुना और भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में कर्मचारियों व मजदूरों की मांगों को मानने की सहमति जताई थी और इन सभी मांगों को बजट में लाने का पूर्ण आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ को दिए गए आश्वासन के अनुसार उसे बजट में रखा और सभी वर्गो को इस बजट में लाभ दिया है जिसकी भारतीय मजदूर संघ सराहना करता है।

सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी में प्रतिदिन 50 की और मासिक में 1500रुपये की बढ़ोतरी की है। जिससे लाखों श्रमिकों तथा दैनिक भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ के मासिक मानदेय में 1700 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 900 तथा सहायिका को 900 की बढ़ोतरी हुई है जिससे 38000 आगनबाडी कार्यकर्ताओं को को लाभ हुआ। वेटरनरी फार्मासिस्ट की घोषणा कर 507 कर्मचारियों को लाभ हुआ।आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 1500 की बढ़ोतरी करना तथा इनके शोषण को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों को पे स्लिप देने की घोषणा से लगभग 40000 कर्मचारियों को लाभ हुआ। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1825 की बढ़ोतरी करके सरकार ने लगभग 8000 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ हुआ। मिड डे मील वर्कर के मानदेय में 900 का इजाफा कर लगभग 22000 मिड डे मिल वर्कर को लाभ हुआ। सिलाई कटाई अध्यापिका के वेतन में 900 का इजाफा करके लगभग 1700 अध्यापिकाओं को लाभ मिला। जलवाहक ,जल रक्षक, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर, राजस्व चौकीदार ,मल्टी वर्कर, राजस्व लंबरदार तथा पंचायत चौकीदारों के मासिक वेतन में 900 की बढ़ोतरी करके सरकार ने लगभग 30000 कर्मचारियों को लाभ दिया। एसएमसी शिक्षकों तथा आई टी शिक्षकों को 1000 प्रति माह की बढ़ोतरी करके लगभग 4000 शिक्षकों को लाभ हुआ। पीस मील वर्करों को अनुबंध में लाकर लगभग 657 कर्मचारियों के भविष्य को उज्जवल किया है। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की मांग को भी पूरा किया। लेकिन करूणामूलक को अपनी मागों को लेकर हड़ताल पर बैठे 200 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है।

भारतीय मजदूर संघ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल करना तथा निगमों बोर्डो एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की 1999 की पेंशन अधिसूचना को बहाल करके पेंशन देने की मांग को भी पूर्ण करने के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। उक्त सभी मांगों को पूर्ण करने के लिए भारतीय मजदूर संघ मुख्यमंत्री तथा सरकार का धन्यवाद करता है।

भारतीय मजदूर संघ मुख्यमंत्री से उम्मीद करता है कि आउट सोर्स, सिलाई कटाई अध्यापिका अंशकालीन राजस्व चौकीदार, आईटी अध्यापकों और एसएमसी शिक्षकों के लिए भी शीघ्र पाल्सी बनायेंगे।